Provision of High Court Benches in *different parts of the country*

4406. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have finalised its policy for providing benches of High Courts in various parts of the country;

(b) if so, what are the details thereof and by when Government propose to start providing benches of different High Courts in different parts of the country;

(c) whether Government propose to create some more benches of the Madhya Pradesh High Court in the State; and

(d) if so, what are the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) and (b) In its report submitted to the Government on 30.4.1985 the Jaswant Singh Commission suggested the broad principles and criteria to be followed while deciding the question of expediency and desirability of establishment of a bench of a High Court away from the principal seat and the factors to be kept in view in selecting the venue of the said bench. The report of the Commission was placed in the Parliament Library on 15.10.1986 and was laid on the Table of the Rajya Sabha and Lok Sabha on 20.4.1987 and 21.4.1987 respectively, which may be referred to. The question of opening a High Court Bench is considered by the Central Government in the light of these principles and criteria as and when a proposal is received from the State Government in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court.

(c) and (d) The Central Government can consider the question of establishing more benches of Madhya Pradesh High Court away from its principal seat only if a specific and complete proposal is received from the Government of Madhya Pradesh, in consultation with the Chief Justice of the High Court. No such proposal has been received in the light of recommendations of the Jaswant Singh Commission for establishing a High Court Bench at Raipur.

उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाएं

4407. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं में भी न्यायालय का कार्य किया जाता है; और

(ख) इन न्यायालयों में किन-किन भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 348(1) में यह उपबंध है कि जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। अनुच्छेद 348(2) के अधीन, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों, आदि के प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया जा सकेगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चार राज्यों, अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों ने अपने-अपने राज्यों में उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों के साथ-साथ निर्णयों, डिक्रियों, आदि में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को भी प्राधिकृत किया है।